Amount Allocated for the Development orks in H P , A *V* , Mizoram, Nagaland, Sikkim

6346 DR. MURLI MANOHAR JOSHI;

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the amount allocated - to Manachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Sikkim - and Jammu and Kashmir for development works in the Seventh Five Year Plan and what is 'the actual amount spent by each of the Sates;

(b) the amount allocated to each of the above Sites for development in 1993 and proposed in 1994 and the amount actually utilised by each State in 1993; and

(c) the demand made by each of the above States for development funds in 1993 and for 1994?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Table I indicating approved outlay and actual expenditure for the concerned States for the Seventh Five Year Plan (1985—90)-myearwise—is attached [*See* Appendix 170, Annexure No. 129]

(b) and (c) The amount proposed by these States and amount allocated to them during 1993-94 and 1994-95; alongwith their revised outlays for 1993-94, is at Annexure *[See* Appendix 170, Annexure No. 130].

मजदूर वर्गों में शिक्षा का अत्यधिक विस्तार किया जाना

6347. श्री राम जेठमलानी :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, के "पाइनर" में प्रकाशित "एजुकेशन की टू हाइ ग्रोथ डब्ल्यू बी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए विशेषकर श्रमिक वर्गों में शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार देश की योजनाओं में शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता की सूची में रखने का विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क), (ख) और (घ) सरकार शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए वचनबद्ध है जो मानव संसाधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है ।

(ग) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

Incomplete Irrigation Projectg in Maharashtra

6348. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number of large and medium irrigation projects approved by Government in the State of Maharashtra, which have not yet been completed;

(b) what are the reasons for delay in their completion;

(c) what were the Budget Estimates of estimates as on 1-3-94; and
these projects and what are the revised

(d) how much further delay is envisaged in completion of the projects and what will be the further revised estimates in respect thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PRO GRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GERIDHAR GOMANGO: (a) to (d) Irrigation and Flood Control is in the State List of the Constitution and as such the concerned State is primarily responsible for investigation, formulation, Planning, execution, financing and management of irrigation projects. The funding priority for irrigation projects is to be determined by the State Governments themselves within their available resources in the Annual Plans. As of now, 52 approved major and medium irrigation projects are under various stages of construction in the State of Maharashtra. The approved outlay under major and medium irrigation sector for 1993-94 was Rs. 568. 28 crores whereas the revised approved outlay was Rs. 596.37 crores.

उत्तर प्रदेश से पिछड़ेपन का हटाया जाना

6349. मौलाना मोबैदुल्ला खान आजमी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने का विचार रखता है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का आवंटन संबंधी फार्मूला उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बन रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के साथ हाल ही में कोई बात हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारतीय आयोजना का प्रमुख लक्ष्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के पिछड़ेपन को दूर करना तथा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न सेक्टरों में विकास कार्यक्रमों तथा स्कीमों के क्रियान्वयन के माध्यम से इसे प्राप्त करना है।

(ख) जी, नहीं । इसके विपरीत जनसंख्या तथा आय मानदंड (अर्थात् राष्ट्रीय औसत से नीचे राज्य की प्रति व्यक्ति आय) के आधार पर वांछित केन्द्रीय योजना सहायता उपलब्ध कराने वाला यह फार्मूला उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को उचित महत्व देता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) हाल ही में इस विषय पर कोई विशिष्ट चर्चा नहीं हुई है । यद्यपि राज्य की वार्षिक योजना (1994–95) प्रस्तावों पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जनवरी–फरवरी, 1994 में विचार विमर्श हुआ था ।

Recommendation of Krishnaswamy Ciwmittee Report

6350. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of PLANNING AND PRO GRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether a Conference of Voluntary Organisations was held in March, 1994 which made certain suggestions and recommendations to government for their smooth functioning;

(b) if so, what are their main recommendations and reaction of government thereto;

(c) whether government have since for mulated some policy for the Voluntary Sector if so, details thereof; and